

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक-28 सितम्बर, 2011

विषय : नगर पंचायत, कर्णप्रयाग के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष-2005-06 में स्वीकृत निर्माण कार्य हेतु की चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं० 470/V-श0वि-06-45(सा0)/06 दिनांक 6-3-2006 के क्रम में शासनादेश संख्या 1880/IV(2)-श0वि0-09-45(सा0)/06 दिनांक 4-1-2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिनके माध्यम से नगर पंचायत, कर्णप्रयाग के अन्तर्गत ₹ 74.09 लाख की प्रशासकीय प्रदान करते हुए क्रमशः ₹ 33.01 लाख तथा ₹ 24.17 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें अपर बाजार कर्णप्रयाग में पार्किंग स्थल के निर्माण हेतु ₹ 52.38 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए क्रमशः ₹ 11.00 लाख एवं ₹ 24.17 लाख, अर्थात् कुल ₹ 35.17 लाख (₹ पैंतीस लाख सतरह हजार मात्र) अवमुक्त किया गया था।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष, नगर पंचायत, कर्णप्रयाग के पत्र संख्या 67/अव0वि0नि0./2011-12 दिनांक 8-6-2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 6-3-2006 तथा शासनादेश दिनांक 4-1-2010 के क्रम में अपर बाजार कर्णप्रयाग में पार्किंग स्थल के निर्माण हेतु प्राप्त न्यूनतम निविदा ₹ 0.12 लाख का समायोजन करते हुए अवशेष ₹ 17.01 लाख (₹ सत्रह लाख एक हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि ₹ 17.01 लाख (₹ सत्रह लाख एक हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित नगर पालिका परिषद को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जो शासनादेश की शर्तें पूर्ण करने पर कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करेंगे।
2. शासनादेश संख्या 470/V-श0वि-06-45(सा0)/06 दिनांक 6-3-2006 में उल्लिखित अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
4. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
5. कार्य के मध्य तथा बाद में इसकी गुणवत्ता की चेंकिंग, किसी तृतीय तकनीकी पक्ष से कराके उसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित किया जायेगा और इसका खर्च योजना की अनुमोदित लागत से ही वहन किया जायेगा।

6. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
7. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
8. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
9. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनोद्देश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
10. स्वीकृत कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि का दिनांक 31-3-2012 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्यय के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05- नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0- 303/XXVII(2)/2011, दिनांक- 14 जुलाई, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

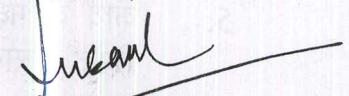
(डा० रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

सं०- 812 (1)/IV(2)-शा०वि०-11, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. जिलाधिकारी, चमोली।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कर्णप्रयाग।
9. वित्त अनुभाग-2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी०ओ० में इसे शामिल करें।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,


(सुभाष चन्द्र)
रत्न स्मृति।